राजस्थान–सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांकःएफ.8(1)वित्त/नियम/2020 जयपुर, दिनांकः 20 MAY 2020

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष ।

परिपत्र

विषयः–वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.14(1)वित्त(नियम)/2013 दिनांक 30.10.2017 के संबंध में तथ्यात्मक विवरण।

1. अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में निम्नानुसार संशोधन किये गये, जोकि दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी हैं:–

"2. **Amendment of Schedules and Rules:-** In the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008-

(A) The existing Section 'A' Running Pay Band and Grade Pay of Schedule-I under Rules 6 shall be substituted by the Annexure 'A' appended to this Notification.

(B) The existing Schedule IV-Amount of fixed Remuneration for Probationer Trainee under Rules 21 shall be substituted by the Annexure 'B' appended to this Notification.

(C) The existing Schedule V-Entry Pay in the Running Pay Bands and Grade Pays for Direct Recruits Appointed on a or after 01.01.2006 on satisfactory Completion of Probation Period under Rules 22 shall be substituted by the Annexure 'C' appended to this Notification.

(D) (i) In section 'B', 'C' and 'D' of Schedule I, the existing Pay Band, Running Pay Band, Grade Pay No. and Grade Pay wherever appearing in column no. 4, 5, 6 and 7 respectively shall be substituted by the following namely:-

Existing				Revised			
Pay Band	Running Pay Band	Grade Pay No.	Grade Pay	Pay Band	Running Pay Band	Grade Pay No.	Grade Pay
4	5	6	7	4	5	6	7
PB-I	5200-20200	7	2000	PB-I	5200-20200	9A	2400
PB-I	5200-20200	8	2100	PB-I	5200-20200	9B	2400
PB-I	5200-20200	10	2800	PB-I	5200-20200	10A	2800

(E) The existing entries at S.No. 7,8 & 10 of Rule 29 shall be substituted by the following, namely:-

Existing Grade Pay No.	Existing Grade Pay	Pay Band	Running Pay Band	Revised Grade Pay	Grade Pay	Increase in Pay in Running Pay Band
7	2000	PB-1	5200-20200	9A	2400	100
8	2100	PB-1	5200-20200	9B	2400	200
10	2800	PB-1	5200-20200	10A	2800	300

(F) After the existing Rule 29, the following new Rule 30 shall be inserted namely:-

30. Notwithstanding anything contained in these Rules, over payment of pay and allowances thereon made to the Government servants during the period from 01.07.2013 to date of this notification (both days inclusive) shall not be recovered."

2. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.14(1)वित्त(नियम)/2013–II दिनांक 28.06.2013 के द्वारा पूर्व में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में संशोधन किये गये थे। अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 को संशोधित करने हेतु वित्त विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) को प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे। उक्त प्रस्तावों के परीक्षण के क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश सं. एफ. 6(42)प्रशा.सु.–3/ग्रुप–3/2014 दिनांक 17.12.2014 द्वारा प्रस्तावित संशोधनों का परीक्षण किये जाने हेतु समिति का गठन किया गया।

3. उक्त समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 21.06.2017 में अनुसूची–V को त्रुटिपूर्ण माना गया एवं वेतन विसंगति के समाधान की तुरन्त आवश्यकता बताई। वेतन विसंगति के समाधान हेतु प्रतिवेदन में निम्नलिखित सिफारिश की गई:–

"(1) Finance Department to issue directions for rectifying the anomalies wherein senior employees are getting lower salaries than the employees entering the service after them. The cut-off date of such rectification be kept as 30th June, 2017 and the corrected notification be issued immediately and made applicable from 01.07.2017. However, payment made prior to 01.07.2017 pursuant to the erroneous notification dated 28th June, 2013 may not be recovered.

(2) Schedule-V of Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2008 may be amended accordingly so that no benefit is accrued w.e.f. 1st July, 2017.

4. उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंषा को ध्यान में रखते हुये राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 की अनुसूची–V में वित्त (नियम) विभाग की

अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 में संशोधन हेतु मंत्रिमण्डल ज्ञापन प.14(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 03.07.2017 को प्रस्तुत किया गया।

5. उक्त मंत्रिमण्डल ज्ञापन में प्रस्तावित संशोधन के परीक्षण हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा प.5(1)मंमं/2014 दिनांक 21.07.2017 के द्वारा मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन किया गया। मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा वित्त विभाग एवं विभिन्न कर्मचारी संघो से हुई विस्तृत चर्चा कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह एवं अन्य के वाद सीए नं. 11527/2014 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया। उक्त समिति द्वारा अनुसूची–V को पुनः संशोधित किये जाने के प्रस्ताव पर निम्नलिखित सिफारिश की गयी :–

"(1) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 की अनुसूची–V में संशोधन दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी किया जावे।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 की अनुसूची–V में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना प.14(1)वित्त/नियम/2013–II दिनांक 28.06.2013 के द्वारा संशोधन किये जाने के फलस्वरूप जिन कर्मचारियों का दिनांक 01.07.2013 से उक्त अनुसूची–V में निर्धारित वेतन के अनुसार वेतन निर्धारण किया गया है, ऐसे कर्मचारियों का पुनः संशोधित अनुसूची–V के अनुसार दिनांक 01.07.2013 से वेतन निर्धारण किया जावे।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 की अनुसूची–V को दिनांक 01.07.2013 से पुनः संशोधित किये जाने की अधिसूचना जारी करते हुए अगस्त 2017 तक संशोधित वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक प्राप्त वेतन परिलब्धियों की कर्मचारियों से वसूली नहीं की जावे।

(4) वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना प.14(1)वित्त/नियम/2013–II दिनांक 28.06.2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में दिनांक 01.07.2013 से प्रभावी अनुसूची–V को पुनः संशोधित किये जाने की अधिसूचना जारी होने की दिनांक से पूर्व ग्रेड पे रू. 2400/– के कर्मचारियों को प्राप्त वेतन परिलब्धियों (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) एवं केन्द्रीय सातवे वेतन आयोग आधारित पुनरीक्षित वेतन नियमों में वेतन निर्धारण किये जाने पर यदि कर्मचारियों की संशोधित परिलब्धियॉ कम रहती है तो उक्त अन्तर राशि को व्यक्तिगत वेतन के रूप में रखा जावे तथा इस राशि को आगामी वेतनवृद्धि से समायोजित किया जावे।"

6. उपरोक्त सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 जारी की गयी। उक्त अधिसूचना द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में नियम 30 को जोडा गया है, जिसके द्वारा दिनांक 01.07.2013 से दिनांक 30.10.2017 के मध्य की समयावधि में राजकीय कार्मिकों को प्राप्त वेतन एवं भत्तों के अधिक भुगतान की वसूली नहीं की गयी है। इस संबंध में आदेश क्रमांक प.14(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 09.12.2017 (प्रति संलग्न) भी जारी किया गया है जिसके द्वारा वेतन एवं मंहगाई भत्ता के अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया गया है, जिसको कि भविष्य में अर्जित होने वाली वेतन–वृद्धि में समाहित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

7. अतः अनुरोध है कि अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 को चुनौती दिये जाने हेतु दायर की गयी विभिन्न याचिकाओं के संबंध में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावों में उपरोक्तानुसार तथ्यों को सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

20/5/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

(RSR-24/2020)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

ORDER

No. F. 14(1) FD/Rules/2013 Jaipur, dated: 09.12.2017

Subject:- Treating difference as Personal Pay under Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.

Under Finance Department Notification No. F.14(1)FD/Rules /2013-II dated 28.06.2013, the Schedule-V appended to Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules,2008 was substituted with effect from 01.07.2013. The Entry Pay in Running Pay Band and Grade Pays for direct recruits was revised w.e.f. 01.07.2013 erroneously and in certain cases undue excess payment has been authorized.

This issue of erroneous payment was referred to the Committee constituted by Administrative Reforms Department vide order No. F.6(42) AR-3/Gr.3/2014 dated 17.12.2014. The Committee has submitted its report on 21.06.2017 after considering the issue in detail and recommended to rectify the above error.

The matter has been considered and the Governor is pleased to order that in the aforementioned cases firstly pay be fixed from 01.07.2013 to 01.01.2016 as per provisions of Notification No. F.14(1)FD/Rules/2013-II dated 28.06.2013 and again as per revised Notification No.F.14(1)FD/Rules/2013 dated 30.10.2017 from 01.07.2013 to 01.01.2016. The difference of sum of Pay plus Dearness Allowance allowed under Notifications dated 28.06.2013 and 30.10.2017 may be treated as Personal Pay which is to be absorbed in future increases in Pay.

An example of existing fixation of Pay and revised fixation of Pay from 01.07.2013 to 01.01.2016 indicating difference to be treated as Personal Pay which is to be absorbed in future increases in Pay is given below:-

For Grade Pay 2400 (1900)

As on Date	Existing Basic Pay	D.A	Total	Revised Basic Pay	D.A	Total	Difference (Col. 4 – Col. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01.07.2013	9840	8856	18696	8080	7272	15352	3344
01.07.2014	10140	10850	20990	8330	8913	17243	3747
01.07.2015	10450	12436	22886	8580	10210	18790	4096
01.01.2016	10450	13063	23513	8580	10725	19305	4208*

*** The difference of Rs. 4208/- shall be Personal Pay and which is to be absorbed in future increases in Pay.**

Due to above re-calculation no recovery of over payment shall be made as provided in Rule 30 of the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008.

Consequent upon absorption of Personal Pay in increases in pay under Rajasthan Civil Services(Revised Pay) Rules, 2017, the increment withheld under Finance Department Order No.F.14(8)FD/Rules/2013/pt-II dated 28.07.2017 shall be released.

These provisions shall also be applicable to the Work-charged Employees drawing Pay in Rajasthan Work-charged Employees (Revised Pay) Rules, 2008.

Finance Department Order of even number dated 30th October, 2017 shall stand superceded.

By order of the Governor,

(Manju Rajpal)
Secretary to the Government
Finance (Budget)

Copy forwarded to -

1. Secretary to Hon'ble Governor.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister.
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
5. Sr. D.S. to Chief Secretary
6. Accountant General Rajasthan, Jaipur.
7. All Heads of the Departments.
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan
9. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers Office.
10. All Treasury Officers.
11. All Sections of the Secretariat.
12. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
13. Vidhi Rachana Sanghthan, for Hindi translation.
14. Additional Director, Finance Department(Computer Cell)
15. Guard File

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.

09/11/2017

(Mahendra Singh Bhukar)
Joint Secretary to the Government

(RPS - 2008/ 14 /2017)